आकांक्षी ज़िला और ब्लॉक कार्यक्रम
ज़मीनी स्तर पर सशक्तीकरण के ज़रिए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का मॉडल

-सौरभ ऋषि
-शशांक शाह

एडीपी और एबीपी द्वारा सक्षम तीव्र और विकेंद्रीकृत विकास ने नागरिकों के कल्याण और उनकी विकास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक मज़बूत नींव रखी है। दूरदराज के ज़मीनी स्तरों तक पहुँच कर, इन पहलों ने एक समृद्ध और समावेशी राष्ट्र के विज़न को साकार करने की सभी भारतीयों की आकांक्षाओं को उजागर किया है। यह प्रत्येक भारतीय को उम्मीद देता है कि 2047 में 'विकसित भारत' का लक्ष्य प्राप्त करने योग्य वास्तविकता है।

हिमालय में बसा चम्बा हिमाचल प्रदेश का एक उत्तर-पश्चिमी जिला है। प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर होने के बावजूद, ज़िले को अपने पहाड़ी इलाके और कठोर जलवायु परिस्थितियों के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लगभग 5 लाख की आबादी के साथ, जिसमें से 93% ग्रामीण हैं, ज़िले को कम जनसंख्या घनत्व वाले दूरदराज के स्थानों पर लागत प्रभावी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हालांकि पिछले पांच वर्षों के दौरान, चम्बा ने अंतिम मील तक पहुँचने और यह सुनिश्चित करने में काफी प्रगति की है कि कोई भी नागरिक पीछे न छूटे। उदाहरण के लिए जिला प्रशासन ने दूरदराज के स्थानों पर बुनियादी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल मेडिकल इकाइयों की सेवाएं शुरू की हैं। परिणामस्वरूप गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव-पूर्व देखभाल में 70% से 90% तक सुधार हुआ है, और संस्थागत प्रसव 40% से 80% यानी दुगुना हो गया है। इसने क्षेत्र में एमएमआर/आईएमआर पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जन्स) और सीएसआर अनुदानों से चम्बा में सीखने के प्रतिफल में सुधार के लिए सामुदायिक पुस्तकालय और पहाड़ी ढलानों पर सूक्ष्म सिंचाई सुविधाएं भी स्थापित की गई हैं। चम्बा की तरह, कई जिलों को ऐतिहासिक रूप से अपनी

लेखक नीति आयोग, भारत सरकार में वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं। ई-मेल : saurabh.rishi@gov.in; shashank.shah@gov.in

भौगोलिक स्थिति या जनसांख्यिकीय संरचना के कारण अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

भारत एक बहु-सांस्कृतिक राष्ट्र है जो अपनी समृद्ध विविधता से विश्व में अपना एक अलग स्थान रखता है। यह समृद्धि विभिन्न भाषाओं और जीवनशैली में प्रकट होती है। हालाँकि यह विविधता नागरिकों के बीच सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को भी जन्म देती है। जहां कुछ क्षेत्रों में तेजी से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण हो रहा है, वहीं अन्य क्षेत्रों को पिछड़ेपन का सामना करना पड़ रहा है। असमानता के कारण अलग-अलग हैं- कठिन भौगोलिक भू-भाग, संसाधनों की कमी, ऐतिहासिक अन्याय, सामाजिक उपेक्षा और निर्बलता, अकुशल प्रशासन और नागरिक अशांति, आदि। इन मुद्दों से निपटने और समाज के सभी क्षेत्रों और वर्गों में समान सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जनवरी 2018 में जमीनी-स्तर पर बेहतर प्रशासन पर ध्यान देने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी)* लॉन्च किया गया।

उत्पत्ति और परिणाम

आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम-एडीपी की उत्पत्ति भारत के विकास को तीव्र करने के लिए 100 से अधिक पिछड़े ज़िलों के तेजी से विकास के प्रधानमंत्री के विजन में निहित है। इसे प्राप्त करने के लिए नीति आयोग ने आकांक्षी जिला फ्रेमवर्क तैयार किया, जो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अविकसित जिलों (जिन्हें आकांक्षी ज़िला-एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स नाम दिया गया) की पहचान करने के साथ-साथ संतुलित क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक जटिल और वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई प्रक्रिया थी।

व्यापक क्षेत्र दौरों ने, द्वितीयक आँकड़ों के पूरक के तौर पर, प्रासंगिक ज़मीनी-स्तर का डेटा प्रदान किया। इस कठोर चयन ने भारत सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी विकेन्द्रीकृत विकास हस्तक्षेपों में से एक को जन्म दिया। कार्यक्रम लागू करने के पाँच वर्ष बाद, जिसे 112 ज़िलों में एक जन-आंदोलन के रूप में लागू किया गया, ने अभिसरण (योजनाओं के), सहयोग (सभी हितधारकों के बीच) और प्रतिस्पर्धा (जिलों के प्रमुख संकेतकों के बीच) के मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करके सामाजिक-आर्थिक मापदंडों में ज़मीनी-स्तर पर महत्वपूर्ण सुधार किया। 30 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में एकत्रित 3,000 से अधिक क्षेत्रीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि, 'एडीपी सभी योजनाओं में, जिन्हें भारत सरकार ने आजादी के बाद से लागू किया है, शीर्ष 10 की सूची में सुनहरे अक्षरों में अपना स्थान पाएगा।'

नवोन्वेषी एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण

एडीपी ने त्वरित और समावेशी मानवीय विकास के लिए बेहतर प्रशासन पर केंद्रित 'प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद' का एक

*ADP-Aspirational District Programme

> **ज़िलों में कई प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को स्थानीय बनाने में भारत की प्रगति पर बड़ा प्रभाव डाला है। घरेलू बिजली कनेक्शन और व्यक्तिगत शौचालय जैसे कुछ संकेतक अधिकांश आकांक्षी ज़िलों (एडी) में संतृप्ति स्तर के करीब पहुँच गए हैं।**
> -प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, 30 सितम्बर, 2023, भारत मंडपम, नई दिल्ली

नया मॉडल पेश किया। इसने मौसमी साइलो-संचालित योजनाओं को नियमित परिणाम-आधारित समीक्षाओं में बदल दिया। इसने ज़िलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुए, तीन तरीकों से केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया। सबसे पहले, हालांकि नीति आयोग ने इस पहल को केंद्रीय रूप से संचालित किया, राज्य प्राथमिक चालक थे। ज़िला कलेक्टरों ने एकीकृत स्थानीय कार्ययोजना तैयार करते हुए, कमियों को दूर करने के लिए, ज़मीनी-स्तर की भागीदारी को उत्प्रेरित किया। दूसरे, फोकस 'इनपुट' से 'परिणामों' पर स्थानांतरित हो गया। राज्यों के औसत बनाए रखने और अपने राज्य में सर्वश्रेष्ठ बनने की आकांक्षा रखने हेतु ज़िलों के लिए स्पष्ट सफलता मेट्रिक्स परिभाषित किए गए। तीसरा, एडीपी ने बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया। एक रियल टाइम डैशबोर्ड ने स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढांचे सहित पांच क्षेत्रों में, मासिक आधार पर 49 सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को ट्रैक किया। इसने डेटा-आधारित रैंकिंग के माध्यम से निरंतर निगरानी और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को सक्षम किया। इस प्रकार, यह कार्यक्रम डेटा-संचालित प्रशासन के माध्यम से, साक्ष्य-आधारित नीति हस्तक्षेप के एक अद्वितीय मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है।

पिछली पहलों के आधार पर, जिन्होंने इन क्षेत्रों को अनुदानों के साथ समर्थन दिया है, कार्यक्रम का प्राथमिक ध्यान अंतिम मील तक सरकारी सेवा वितरण की संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए ज़िला प्रशासन के स्तर पर क्षमता निर्माण करना है। इसने बुनियादी सेवाओं जैसे पक्के मकान, सभी मौसम के अनुकूल सड़कें, बिजली, नल के पानी के कनेक्शन, लचीली स्वास्थ्य अवसंरचना, वित्तीय समावेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान और आय सृजन में सहायता के लिए कौशल विकास को सक्षम करने के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित किया है।

ज़िलों में कई प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को स्थानीय बनाने में

भारत की प्रगति पर बड़ा प्रभाव डाला है। घरेलू बिजली कनेक्शन और व्यक्तिगत शौचालय जैसे कुछ संकेतक अधिकांश आकांक्षी ज़िलों (एडी) में संतृप्ति स्तर के करीब पहुँच गए हैं।

भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मिशन इंद्रधनुष, स्वच्छ भारत मिशन, पोषण अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित कई अन्य ने एक मज़बूत आधार बनाया जिसने एडीपी के तहत तेज़ी से परिवर्तन को उत्प्रेरित किया और भारत के भीतरी इलाकों में सामाजिक-आर्थिक कल्याण के दृश्यमान विस्तार को सक्षम बनाया।

महत्वपूर्ण सफलता कारक

एडीपी की मुख्य रणनीति ज़मीनी स्तर पर शासन में सुधार के लिए प्रक्रिया पुनर्रचना और नवाचारों पर आधारित है। कुछ महत्वपूर्ण सफलता कारकों में शामिल हैं:

1. सकारात्मक नामकरण : चयनित ज़िलों को 'पिछड़ा' के बजाय 'आकांक्षी' कहा जाता है, क्योंकि वे पहले अपने राज्य में और उसके बाद देश में 'सर्वश्रेष्ठ' बनने की आकांक्षा रखते हैं। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण ज़िला प्रशासन और इन ज़िलों के लोगों में सकारात्मकता की भावना पैदा करना है ताकि वे देश के बाकी हिस्सों के लिए प्रेरणा बन सकें।

2. प्राथमिकता का सिद्धांत : कार्यक्रम प्राथमिकता के सिद्धांत को अपनाता है जो भौगोलिक क्षेत्रों, क्षेत्रों और समुदायों की पहचान करता है। प्राथमिकता वाले सामाजिक-आर्थिक संकेतकों का उपयोग करके एडी का सावधानीपूर्वक चयन किया गया है। इसी प्रकार, समाज के सभी वर्गों के लिए बुनियादी सामाजिक सेवाओं की पहचान की गई है जिन्हें संतृप्त किया जा सकता है।

> "एडीपी स्थानीय क्षेत्र विकास का एक बहुत ही सफल मॉडल है। यह 'किसी को पीछे न छोड़ें' के सिद्धांत से जुड़ा है- जो एसडीजी का महत्वपूर्ण मूल है। इसे कई अन्य देशों के लिए सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में काम करना चाहिए जहां विकास की स्थिति में क्षेत्रीय असमानताएं कई कारणों से बनी हुई हैं।"
>
> -यूएनडीपी

3. शासन में नवाचार : स्थिर कार्यकाल के साथ गतिशील ज़िला प्रशासन के ज़रिए ज़मीन पर तेज़ी से प्रगति करने का सरकार का प्रयास रहा है। एडी ने पारंपरिक चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन समाधान अपनाए हैं। सभी स्तरों पर शीर्ष नेतृत्व की प्रतिबद्धता भी इस प्रगति में एक प्रेरक कारक रही है।

4. प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद : मज़बूत निगरानी और डेटा-संचालित शासन, कार्यक्रम के तहत एक केंद्रीय रणनीति रही है। 49 सामाजिक-आर्थिक प्रदर्शन संकेतक इनपुट, प्रक्रिया, आउटपुट और परिणाम संकेतकों का मिश्रण हैं जो एसडीजी प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक हैं। अधिक विकसित ज़िलों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने और बेंचमार्किंग के लिए एडी को संकेतों में किए गए सुधार के आधार पर समय-समय पर रैंक किया जाता है।

5. क्षैतिज अभिसरण और सहयोग : सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज़िला विभागों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। नागरिक समाज संगठनों और विकास भागीदारों के साथ अभिसरण एक प्रभावी कार्यान्वयन रणनीति रही है।

6. लंबवत सहयोग : यह केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य विभागों और ज़िला प्रशासन के बीच सहयोग पर केंद्रित है। उन्हें सलाह देने और प्रशासनिक स्तरों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक एडी के लिए वरिष्ठ स्तर के केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

7. साथ-साथ सीखना और व्यवहार परिवर्तन : एडी का समुदाय सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और बेंचमार्किंग के माध्यम से एक-दूसरे से लाभान्वित होता है। अंतर-राज्य कार्यशालाओं, क्रॉस-विज़िट और डिजिटल मास्टरक्लास के माध्यम से, समान भौगोलिक क्षेत्रों में पिछड़े ज़िले प्रतिस्पर्धी भावना से अच्छा प्रदर्शन करने वाले सहकर्मी ज़िलों की सफलता और नवाचारों से सीख सकते हैं और उन्हें दोहरा सकते हैं।

इस प्रकार, एडीपी ने इष्टतम संसाधन आवंटन, वास्तविक समय की निगरानी और ज़िला प्रशासन की क्षमता निर्माण के माध्यम से समग्र सुधार को सक्षम किया। यहां तक कि दूरदराज के क्षेत्रों ने भी प्रगति की है और पुष्टि की है कि अगर सामूहिक प्रतिबद्धता मज़बूत हो तो विकास हासिल किया जा सकता है। कार्यक्रम की अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट में, यूएनडीपी ने उल्लेख

किया कि "एडीपी स्थानीय क्षेत्र विकास का एक बहुत ही सफल मॉडल है। यह 'किसी को पीछे न छोड़ें' के सिद्धांत से जुड़ा है– जो एसडीजी का महत्वपूर्ण मूल है। इसे कई अन्य देशों के लिए सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में काम करना चाहिए जहां विकास की स्थिति में क्षेत्रीय असमानताएं कई कारणों से बनी हुई हैं।"

उप-राष्ट्रीय परिवर्तन

एडीपी ने उप-राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और स्केल करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया, ताकि प्राप्त सकारात्मक परिणाम स्थानीय भूगोल और जनसांख्यिकी के अद्वितीय संदर्भ में हों। उदाहरण के लिए, झारखंड में लोहरदगा ज़िला, जोकि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है, ने पहली तिमाही के भीतर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण बढ़ा दिया है। राजस्थान में करौली, अरुणाचल प्रदेश में नामसाई और त्रिपुरा में धलाई जैसे ज़िलों में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत औसतन 40% से बढ़कर 90% से अधिक हो गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जैसे कई ज़िले, जहां 2018 तक 50% से कम बच्चों का टीकाकरण हुआ था, वहां पिछले पांच वर्षों में टीकाकरण दर 90% से ऊपर चली गई है। असम में दरांग, बिहार में शेखपुरा और तेलंगाना में भद्राद्री कोठागुदम में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के प्रतिशत में भारी कमी आई है। असम में गोलपारा और मणिपुर में चंदेल जैसे ज़िलों ने पशु टीकाकरण 85% से अधिक तक बढ़ा दिया गया है।

एडी ने एन एफ एच एस-4 की तुलना में नवीनतम एन एफ एच एस-5 सर्वेक्षण परिणामों में भी महत्वपूर्ण सुधार दिखाया है, खासकर उन संकेतकों में जिन्हें कार्यक्रम में भी ट्रैक किया जाता है। प्रसवपूर्व देखभाल पंजीकरण में, उत्तर प्रदेश और बिहार के एडी में 36% से 56% तक सुधार हुआ है, और मध्य प्रदेश में 47% से 71% तक सुधार हुआ है। संस्थागत प्रसव में उत्तर प्रदेश के ज़िलों में 53% से 79% और बिहार के ज़िलों में 62% से 74% का सुधार हुआ है। एनएएस-2021 सर्वेक्षण के अनुसार, राजस्थान का धौलपुर जिला ग्रेड और विषयों में सीखने के परिणामों में सुधार करने में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों में से एक रहा है। जबकि कुछ एडी ने विशिष्ट क्षेत्रों में पर्याप्त सफलता हासिल की है, कुछ अन्य ने समग्र परिवर्तन और कई मापदंडों पर शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में रैंक हासिल की है। इनमें गुजरात में दाहोद, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर (कडपा), तमिलनाडु में विरुधुनगर और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में बारामूला शामिल हैं। सामुदायिक भागीदारी और संसाधनों का लाभ उठाने वाले संदर्भ-विशिष्ट समाधानों ने अधिकांश एडी को उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।

विकास को और विकेंद्रीकृत करने और एडीपी की सफलता को और आगे बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री ने भारत के सबसे कठिन और अविकसित ब्लॉकों में योजनाओं की 100% संतृप्ति कवरेज के लिए स्थानीय योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जनवरी 2023 में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम (एबीपी) लॉन्च किया। एबीपी में ब्लॉकों का चयन मानव विकास के प्रमुख पहलुओं को कवर करने वाले विभिन्न मापदंडों और संकेतकों के आधार पर किया गया।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम

हालाँकि एडी ने अच्छी प्रगति की है, फिर भी विकास के मामले में अंतर-जिला भिन्नता मौजूद है क्योंकि कई ज़िले क्षेत्रफल या जनसंख्या के मामले में बहुत बड़े हैं। विकास खंड यह सुनिश्चित करते हैं कि विकास का आनुपातिक हिस्सा आबादी के हाशिए पर और कमजोर वर्गों तक पहुँचे। ब्लॉक यह सुनिश्चित करता है कि 'एक आकार-सभी के लिए फिट' दृष्टिकोण लागू नहीं किया जाए। इसके बजाय, क्षेत्र की ज़रूरतों के आधार पर अनुकूलित दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया को ज़मीन से भी जोड़ा जा सकता है।

विकास को और विकेंद्रीकृत करने और एडीपी की सफलता को और आगे बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री ने भारत के सबसे कठिन और अविकसित ब्लॉकों में योजनाओं की 100% संतृप्ति कवरेज के लिए स्थानीय योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जनवरी 2023 में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम (एबीपी) लॉन्च किया। एबीपी में ब्लॉकों का चयन मानव विकास के प्रमुख पहलुओं को कवर करने वाले विभिन्न मापदंडों और संकेतकों के आधार पर किया गया। 500 आकांक्षी ब्लॉक (एबी) का चयन राज्यों के परामर्श से एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा किया गया है और ये 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 329 जिलों में स्थित हैं। इनमें से लगभग आधे ब्लॉक पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में हैं। चयन में आदिवासी ज़िलों और पूर्वोत्तर राज्यों के ब्लॉक भी शामिल हैं। लगभग एक-तिहाई

एबी 112 एडी में हैं और दो-तिहाई 217 अन्य जिलों में हैं, इस प्रकार देश के लगभग आधे ज़िले कवर होते हैं।

एडीपी की तर्ज पर, एबीपी के तहत मुख्य रणनीति सामाजिक विकास (सामाजिक विकास) और क्षेत्रीय विकास (क्षेत्रीय विकास) सुनिश्चित करने के लिए ज़मीनी स्तर पर बेहतर प्रशासन और कार्यान्वयन के माध्यम से बुनियादी सेवा वितरण को मज़बूत करना है। इसे निम्नलिखित तरीकों से हासिल किया जाएगा:

1. क्षमता निर्माण : योजनाओं का प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एबीपी ब्लॉक-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) का निरंतर क्षमता निर्माण सुनिश्चित करता है। क्षमता निर्माण मॉड्यूल और मास्टर प्रशिक्षकों को तैयार करना एबीपी का एक केंद्रीय हिस्सा रहा है। पिछली दो तिमाहियों में भारत भर में ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों को 'परिवर्तन' के नेता के रूप में विकसित करने के लिए आयोजित किए गए नेतृत्व प्रशिक्षण से लगभग 5,000 बीएलओ लाभान्वित हुए हैं। इस प्रकार, एडीपी में अपनाए गए ज़िला-संचालित दृष्टिकोण के विपरीत, एबीपी बीएलओ को सशक्त बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है।

2. ब्लॉक विकास रणनीति : एबीपी एक मज़बूत ब्लॉक विकास रणनीति (बीडीएस) विकसित करने के लिए ब्लॉकों का समर्थन करता है। एबी एक एसडब्ल्यूओटी (SWOT) विश्लेषण करते हैं और कमज़ोरियों और खतरों को दूर करने के तरीकों और उपायों को विकसित करते हुए शक्ति और अवसरों को अधिकतम करने के लिए रणनीति तैयार करते हैं। एबी स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और संबद्ध सेवाओं, बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास सहित पांच क्षेत्रों में 40 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) में महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों की भी पहचान करते हैं, जो सेवाओं की संतृप्ति हासिल करने और राज्य के औसत से आगे निकलने में मदद कर सकते हैं। बीडीएस चिंतन शिविरों के माध्यम से और कई सामाजिक हितधारकों के परामर्श से तैयार किया जाता है। जागरूकता फैलाने और व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए अक्टूबर 2023 में 500 एबी की 20,000 ग्राम पंचायतों में एक सप्ताह का 'संकल्प सप्ताह' आयोजित किया गया।

3. ज्ञान पोर्टल : कार्यक्रम में सर्वोत्तम प्रथाओं के दस्तावेज़ीकरण और प्रसार के लिए एक ज्ञान पोर्टल शामिल है। सभी राज्य, ज़िले और ब्लॉक नियमित रूप से ज्ञान पोर्टल पर अपनी ज़मीनी-स्तर की सीख, नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं का योगदान देंगे। कार्यक्रम के तहत निरंतर सीखने के लिए ज्ञान प्रबंधन के अंतर्गत एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

4. संस्थागत सहायता : कार्यक्रम कार्यान्वयन में ब्लॉक और ज़िला प्रशासन की सहायता के लिए प्रत्येक एबी में, तकनीकी सहायता के साथ, एक आकांक्षी ब्लॉक फेलो का प्रावधान किया गया है। प्रशासन के सभी स्तरों के लिए शासन में नवाचारों के लिए पुरस्कार और मान्यता की भी एबीपी के तहत परिकल्पना की गई है।

मुख्य चालक के रूप में राज्यों के साथ कार्यक्रम प्रत्येक एबी के सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा, तत्काल सुधार के लिए कार्यान्वयन योग्य कार्यों की पहचान करेगा, प्रगति को मापेगा और ब्लॉकों को रैंक करेगा।

आकांक्षी और आत्मनिर्भर गाँव

एडीपी द्वारा सक्षम परिवर्तन और एबीपी के तहत शुरुआती फायदे इस बात को रेखांकित करते हैं कि सशक्त और प्रेरित नेतृत्व, हाइपर-स्थानीय योजना, परिणाम-केंद्रित रियल टाइम मॉनीटरिंग और अभिसरण (कन्वर्जेंस) के माध्यम से इष्टतम संसाधन उपयोग विकास को गति दे सकता है। हालाँकि सामुदायिक भागीदारी अभी भी आधारशिला बनी हुई है क्योंकि ज़िलों में संतोषजनक सुधार देखा गया है जहाँ लोग न केवल लाभार्थी थे बल्कि परिवर्तन के सक्रिय प्रतिनिधि थे। कार्यक्रमों की सफलता के लिए 'सबका प्रयास' उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 'सबका विकास'।

एडीपी और एबीपी द्वारा सक्षम तीव्र और विकेंद्रीकृत विकास ने नागरिकों के कल्याण और उनकी विकास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक मज़बूत नींव रखी है। दूरदराज के ज़मीनी स्तरों तक पहुँच कर, इन पहलों ने एक समृद्ध और समावेशी राष्ट्र के विज़न को साकार करने की सभी भारतीयों की आकांक्षाओं को उजागर किया है। महात्मा गाँधी का मानना था कि भारत की आत्मा इसके गाँवों में रहती है। आकांक्षी ज़िलों और ब्लॉकों की यात्रा की परिणति आकांक्षी और आत्मनिर्भर गाँव के रूप में होगी। यह प्रत्येक भारतीय को उम्मीद देता है कि 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने योग्य वास्तविकता है। एक सामाजिक-आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर गाँव अमृतकाल के विज़न को साकार करने की नींव है। ❑